संख्या - 345/V-2011-34(आ0)/2008

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा म

 उपाध्यक्ष,
 नेसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून/हरिद्वार।
 सचिव,

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून/हरिद्वार/गंगोत्री। 2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4— नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 27. मार्च, 2012

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के निर्गत होने से पूर्व लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—2009—V-2011—55(आ0) / 2006टी०सी०, शासनादेश संख्या—2010—V-2011—55(आ0) / 2006टी०सी, शासनादेश संख्या—2012—V-2011—55(आ0) / 2006 टी०सी०, एवं अधिसूचना संख्या—2011—V-2011—55(आ0) / 2006

टी०सींट समदिनांकित 17-11-2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र में भवन मानचित्र एवं परियोजनाओं के स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रकरण, जो उक्त उपविधि / विनियम—2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व से प्राधिकरणों में लिम्बत है, का निस्तारण पूर्व में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ / विनियमों के अनुसार ही किया जाये, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत मामलों के सम्बन्ध में उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 17-11-2011 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा) प्रमुख सचिव

संस्था - 345 (1) / V-2012-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।

अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून। 3.

निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून। 4.

गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा०बी०वी०आर०सी० पुरूषोत्तम अपर सचिव